प्रेस विज्ञप्ति

नौवीं ऐनुअल स्टेटस ऑफ़ एज्युकेशन रिपोर्ट (असर 2013) जारी
नई दिल्ली, 15 जनवरी 2014

ऐनुअल स्टेटस ऑफ़ एज्युकेशन रिपोर्ट, असर 2013, आज नई दिल्ली में योजना आयोग के उपाध्यक्ष श्री मोंटेक सिंह अहलूवालिया द्वारा जारी की गई | यह नौवीं वार्षिक रिपोर्ट है |

असर ग्रामीण भारत में बच्चों का सबसे बड़ा वार्षिक घरेलू सर्वेक्षण है जो कि स्कूली शिक्षण स्थिति और बुनियादी अधिगम स्तर पर ध्यान केंद्रित करता है | प्रथम की मदद से, असर ग्रामीण ज़िलों में स्थानीय संगठनों और संस्थाओं के द्वारा किया जाता है | असर, 2013 में 550 ज़िलों, लगभग 16,000 गाँवों, 3.3 लाख परिवारों और 3-16 वर्ष के 6 लाख बच्चों तक पहुँचा |

असर से हर वर्ष यह पता चलता है कि क्या ग्रामीण भारत में बच्चे स्कूल जाते हैं, वे सरल पाठ पढ़ सकते हैं और बुनियादी गणित कर सकते हैं? 2005, 2007 और 2009 से प्रत्येक वर्ष, असर में हर सैंपल किए गए गाँव में एक सरकारी स्कूल का अवलोकन भी शामिल है | 2010 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE Act) लागू होने के बाद से, असर में किए गए स्कूलों के अवलोकन में शिक्षा के अधिकार में निर्दिष्ट ऐसे मानकों और मानदंडों के अनुपालन से सम्बंधित संकेतकों को भी शामिल किया गए हैं जो कि आसानी से मापे जा सकते हैं | इस वर्ष असर में 14,724 सरकारी स्कूलों का अवलोकन किया गया है|

असर 2013: मुख्य निष्कर्ष

नामांकन 6-14 आयु वर्ग में लगातार उच्च स्तर पर बना हुआ है. इस आयु वर्ग के 96% से अधिक बच्चे विद्यालय में नामांकित हैं | 11-14 आयु वर्ग की लड़कियों में उन लड़कियों का अनुपात जो विद्यालय से बाहर हैं, पिछले वर्ष से कम हुआ है |

कुल मिलाकर, नामांकन के आँकड़े अपने उसी उच्चतम स्तर पर स्थिर है | 6-14 आयु वर्ग में 96% से अधिक बच्चे विद्यालय में नामांकित हैं | यह लगातार पाँचवा वर्ष है जब नामांकन स्तर 96% या उससे अधिक है |

राष्ट्रीय स्तर पर, 11-14 आयु वर्ग की लड़कियों में उन लड़कियों का अनुपात जो विद्यालय में नामांकित नहीं हैं 2012 में 6% से गिरकर 2013 में 5.5% हो गया है | सबसे बड़ा सुधार उत्तर प्रदेश में दिख रहा है, जहाँ यह प्रतिशत 2012 में 11.5% से गिरकर 2013 में 9.4% हो गया | लेकिन, राजस्थान में 11-14 आयु वर्ग की लड़कियों में उन लड़कियों का अनुपात जो विद्यालय से बाहर हैं लगातार दूसरे वर्ष में बढ़ा है | यह अनुपात 2011 में 8.9% से बढ़कर 2012 में 11.2% और अब 2013 में 12.1% तक पहुँच चुका है |

राष्ट्रीय स्तर पर, निजी विद्यालयों के नामांकन में 2012 की तुलना में इस वर्ष थोड़ी-सी वृद्धि हुई है | शुल्क देकर निजी ट्यूशन लेने वाले बच्चों का अनुपात भी पिछले वर्ष से थोड़ा बढ़ा है |

6 से 14 आयु वर्ग के लिए, निजी विद्यालयों के नामांकन में एक स्थिर बढ़ोतरी हुई है, 2006 में 18.7% से बढ़ कर 2013 में 29% हो गई है | पिछले वर्ष से निजी विद्यालयों के नामांकन में बहुत कम वृद्धि हुई है, 2012 में 28.3% से 2013 में 29%|

ग्रामीण भारत में निजी विद्यालयों के नामांकन में व्यापक विविधताएं हैं | मणिपुर और केरल में 6-14 आयु वर्ग के दो तिहाई से अधिक बच्चे निजी विद्यालयों में नामांकित हैं | त्रिपुरा (6.7%), पश्चिम बंगाल (7%) और बिहार (8.4%) में 10% से कम बच्चे निजी विद्यालयों में नामांकित हैं, हालाँकि यह आँकड़े 2006 से तेज़ी से बढ़े हैं |

अलग-अलग राज्यों में, निजी विद्यालयों में नामांकन की तरह, निजी ट्यूशन की दर भी अलग-अलग हैं | त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में, कक्षा 1-5 के 60% से अधिक बच्चे शुल्क देकर निजी ट्यूशन लेते हैं | छत्तीसगढ़ और मिज़ोरम में 5% से कम बच्चे ऐसा करते हैं |

कक्षा 1-5 के बच्चों में उन बच्चों का अनुपात जिन्हें उनके शिक्षण में किसी प्रकार का निजी इनपुट मिलता है (जैसे वे बच्चे जो निजी विद्यालय में पढ़ते हैं, निजी ट्यूशन लेते हैं या दोनों) 2010 में 38.5% से, 2011 में 42%, 2012 में 44.2% और 2013 में 45.1% तक बढ़ा है |

पहली बार, असर 2013 ने, वह राशि भी पता की है जो एक परिवार अपने एक बच्चे के निजी ट्यूशन पर खर्च करती है | राष्ट्रीय स्तर पर, सरकारी विद्यालयों में कक्षा 1-5 के निजी ट्यूशन जाने वाले 68.4% छात्र प्रति माह 100 या उससे कम रुपये देते हैं | निजी विद्यालयों में कक्षा 1-5 के ट्यूशन जाने वाले बच्चों में, 36.7% छात्र प्रति माह 100 रुपये या उससे कम देते हैं और यही अनुपात निजी ट्यूशन के लिए 101 से 200 रुपये प्रति माह के बीच देते हैं|

पिछले वर्ष से बच्चों के पढ़ने की क्षमता में कोई विशेष प्रगति नहीं दिख रही है |

राष्ट्रीय स्तर पर, कक्षा 3 में उन बच्चों का अनुपात जो कम से कम कक्षा 1 के स्तर का अनुच्छेद पढ़ सकते हैं थोड़ा सा बढ़ा है, 2012 में 38.8% से बढ़कर 2013 में 40.2% हो गया है| यह वृद्धि मुख्य रूप से निजी विद्यालयों में नामांकित बच्चों हुई प्रगति से आ रही है | सरकारी विद्यालयों की कक्षा 3 के बच्चों में कक्षा 1 स्तर का पाठ पढ़ सकने वाले बच्चों का अनुपात 2012 से नहीं बदला है और यह लगभग 32% पर ही स्थिर है |

वे राज्य जो 2009 से कक्षा 3 के छात्रों के पढ़ने की क्षमता में स्थिर प्रगति दिखा रहे हैं - वे हैं जम्मू कश्मीर और पंजाब |

राष्ट्रीय स्तर पर, कक्षा 5 के छात्रों में कक्षा 2 स्तर का पाठ पढ़ सकने वाले छात्रों का अनुपात 2012 से लगभग स्थिर बना हुआ है जो कि 47% है | यह अनुपात 2009 से 2012 तक हर वर्ष कम हुआ है, 2009 में 52.8% से गिरकर 2012 में 46.9% हो गया है| सरकारी विद्यालयों में कक्षा 5 के बच्चों में उन बच्चों का प्रतिशत जो कक्षा 2 स्तर का पाठ पढ़ सकते हैं 2009 में 50.3% से गिरकर 2011 में 43.8% और 2013 में 41.1% हो गया है |

2013 में, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, मिज़ोरम और केरल में सरकारी विद्यालयों में कक्षा 5 में 60% से अधिक बच्चे कक्षा 2 के स्तर का पाठ पढ़ सकते हैं | समय के साथ, जम्मू कश्मीर और गुजरात में सरकारी विद्यालयों के कक्षा 5 के छात्रों के पढ़ने के स्तर में सुधार हुआ है |

बच्चे अभी भी बुनियादी गणित में संघर्ष कर रहे हैं

राष्ट्रीय स्तर पर, कक्षा 3 में दो अंकों का हासिल वाला घटाव कर सकने वाले छात्रों के अनुपात में पिछले वर्ष से कोई बदलाव नहीं दिखाई दे रहा है | इस स्तर का गणित कई राज्यों में कक्षा 2 के पाठ्यक्रम का भाग है |

2010 में, निजी विद्यालयों में कक्षा 3 के 47.8% छात्रों की तुलना में, सरकारी विद्यालयों में कक्षा 3 के 33.2% छात्र घटाव या उससे अधिक स्तर का प्रश्न कर पाए हैं | सरकारी और निजी विद्यालयों के बच्चों के बीच का अंतर समय के साथ बढ़ा है | 2013 में, निजी विद्यालयों में कक्षा 3 के 44.6% छात्रों की तुलना में, सरकारी विद्यालयों में कक्षा 3 के 18.9% छात्र घटाव या उससे अधिक स्तर का प्रश्न कर पाए | इन बदलावों के बावजूद, बच्चों के पढ़ने का स्तर नीचा है जो कि चिंताजनक स्थिति है |

राष्ट्रीय स्तर पर, कक्षा 5 के छात्रों में उन छात्रों का अनुपात जो तीन अंकों का एक अंक से भाग का प्रश्न कर सकते हैं, में थोड़ी सी वृद्धि हुई है, 2012 में 24.9% से 2013 में 25.6% | आमतौर पर, इस तरह के भाग के प्रश्न कई राज्यों में कक्षा 3 या कक्षा 4 के पाठ्यक्रम में शामिल हैं|

2013 में, सरकारी विद्यालयों के कक्षा 5 में 20.8% छात्र इस स्तर का भाग कर सके | निजी विद्यालयों में यह आँकड़ा 38.9% है | गणित में, बच्चों का एक बड़ा अनुपात उन स्तरों से काफ़ी वर्ष पीछे है जहाँ उन्हें होना चाहिए |

2013 में, तीन राज्यों (हिमाचल प्रदेश, पंजाब और मिज़ोरम) में सरकारी विद्यालयों में कक्षा 5 में 40% से अधिक छात्र तीन अंकों का एक अंक से भाग के प्रश्न करने में सक्षम रहे|

विद्यालय अवलोकन: असर 2013 के दौरान, ग्रामीण भारत में प्राथमिक कक्षाओं वाले 14724 सरकारी विद्यालाओं का अवलोकन किया गया |

शिक्षक उपस्थिति स्थिर बनी हुई है, परन्तु छात्र उपस्थिति गिरी है|

प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की उपस्थिति में 2012 के 85% की तुलना में कोई बदलाव नहीं दिख रहा है | परन्तु बच्चों की उपस्थिति में थोड़ी सी गिरावट नज़र आ रही है, विशेषतः उच्च प्राथमिक विद्यालयों में जहाँ 2012 में 73.1% थी, से गिरकर 2013 में 71.8% हो गई है |

सरकारी प्राथमिक शिक्षण क्षेत्र में "छोटे विद्यालयों" का अनुपात बढ़ रहा है |

2010 से उन विद्यालयों का अनुपात स्थिर रूप से बढ़ा है जिनका कुल नामांकन 60 छात्र या उससे कम है, 2010 में 27.3% से 2013 में 33.1% हुआ है | इसका अर्थ यह है कि भारत में सभी सरकारी प्राथमिक विद्यालयों के लगभग एक तिहाई विद्यालय "छोटे विद्यालय" हैं | जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखं□, मेघालय, मणिपुर और मिज़ोरम में यह आँकड़ा 60% से अधिक है | 2010 से अब तक की अवधि में 8 राज्य छोटे विद्यालयों के अनुपात में 10 प्रतिशत बिन्दुओं से अधिक की वृद्धि दिखा रहे हैं |

शिक्षा के अधिकार (RTE) के अधिकांश मापने योग्य मानकों का अनुपालन बढ़ रहा है |

उन विद्यालयों का अनुपात जो शिक्षा के अधिकार के छात्र-शिक्षक अनुपात (PTR) मानकों का अनुपालन करते हैं, प्रत्येक वर्ष बढ़ा है, 2010 में यह आंकड़ा 38.9% था जो कि 2013 में 45.3% हो गया है |

उन विद्यालयों का अनुपात जिनमें कार्यालय/भं□ार, खेल का मैदान और बाहरी दीवार है, 2012 के स्तर से थोड़ा सा बढ़ा है |

विद्यालयों में पेयजल के सन्दर्भ में, असर के अवलोकनों में न सि□ यह देखा जाता है कि पेयजल की सुविधा थी बल्कि यह भी देखा जाता है कि सर्वेक्षण के दिन पेयजल उपलब्ध था या नहीं | कुल मिलाकर, उन विद्यालयों का प्रतिशत जिनमें पेयजल की कोई सुविधा नहीं है 2010 में 17% से गिरकर 2013 में 15.2% हुआ है | 7 राज्यों में जहाँ सर्वेक्षण हुए हैं उन में 80% से अधिक विद्यालयों में पेयजल की सुविधा भी थी और पेयजल उपलब्ध भी था | ये राज्य हैं हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, केरल और कर्नाटक |

2010 से उन विद्यालयों के अनुपात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है जिनमें उपयोग करने योग्य कम से कम एक शौचालय है, 2010 में 47.2% से बढ़ कर 2013 में 62.6% हुआ है | 2010 में, अवलोकन किये गए सभी विद्लायाओं में 31.2% विद्यालाओं में लड़कियों के लिए अलग शौचालय नहीं था | 2013 में यह आँकड़ा गिरकर 19.3% हो गया है | लड़कियों के लिए उपयोग योग्य शौचालयों का प्रतिशत भी 2010 में 32.9% से बढ़कर 2013 में 53.3% हुआ है |

पिछले तीन वर्षों में, जहाँ सर्वेक्षण किये गए, उन विद्यालयों में पुस्तकालयों के प्रावधान में स्थिर प्रगति हुई है | राष्ट्रीय स्तर पर, उन विद्यालयों का प्रतिशत जिनमें पुस्तकालय का प्रावधान नहीं है, 2010 में 37.4% से गिरकर 2013 में 22.9% हुआ है |

असर 2013 के दौरान, राष्ट्रीय स्तर पर, सर्वेक्षण के दिन 87.2% विद्यालयों में मध्याह्न भोजन का परोसा जाना देखा गया है| इस वर्ष, 14 राज्यों में, अवलोकन किये गए विद्यालयों में 90% से अधिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन देखा गया है|

संतोषजनक शिक्षण स्तर सुनिश्चित किए बिना शिक्षा की गारंटी अर्थहीन है | यदि बुनियादी शिक्षण स्तरों में जल्द ही सुधार नहीं हुआ तो इस से देश में समानता और विकास पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है |

2012 से भारत की प्राथमिक शिक्षा नीति की रूपरेखा बदल रही है, अब ध्यान सीखने पर अधिक दिया जा रहा है| 12वीं पंचवर्षीय योजना के 'शिक्षा' अध्याय में लिखा है कि "सभी कक्षाओं में शिक्षण स्तर की वृद्धि पर विशेष ध्यान दिया जाएगा"|

2014-15 स्कूली वर्ष की परियोजना प्रक्रिया के लिए SSA से भी अतिरिक्त दिशा-निर्देश दिए गए हैं जिन में सभी राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों में ऐसी योजनाएं बनाएं जिनसे बच्चों के शिक्षण स्तर में वृद्धि हो|

12.1 से
12वीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य:
स्कूली शिक्षा के हर स्तर पर शिक्षण परिणामों में सुधार जो मापा जा सके, जिसका आंकलन किया जा सके और जिसे रिपोर्ट किया जा सके ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कक्षा 2 तक हर बच्चा बुनियादी पढ़ने और गणित के स्तर में निपुण है और वह आलोचनात्मक ढंग से सोच सके, व्यक्त कर सके और कक्षा 5 तक के प्रश्नों को हल कर सके |

राज्यों द्वारा योजनाएं बनाना, उन्हें क्रियान्वित करना और उनका मूल्यांकन करना चुनौतीपूर्ण होगा -

- विभिन्न स्तरों के लिए शिक्षा के लक्ष्य क्या होंगे?
- इन लक्ष्यों को क्रियान्वित करने के लिए क्या ठोस योजनाएं बनाई जाएंगी?
- योजनाओं को कैसे लागू किया जाएगा?
- इनकी प्रगति का मूल्यांकन कैसे किया जाएगा?

शिक्षण स्तर पर केंद्रित शिक्षा नीति के संदर्भ में हम यह उम्मीद करते हैं कि अगले कुछ सालों में बच्चों के शिक्षण पर इन बदलावों का अच्छा प्रभाव पड़ेगा|